तमिलनाडू राज्य जरिए निरीक्षक पुलिस सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक

बनाम

एन सुरेश राजन व अन्य

(आपराधिक अपील सं22-23/2014)

जनवरी 6, 2014

[न्यायाधिपति चन्द्रमौली केप्रसाद व एमवायइकबाल]

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

धारा 239- अभियुक्त का उन्मोचन-आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार के चरण में, अदालत को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए करना होगा कि क्या तथ्य सही है-इस स्तर पर, सामग्रियों के संभावित मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए और अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले की गहराई में जाकर यह मान ले कि ये सामग्रियां दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देंगी।-आक्षेपित आदेशों को पा रित करते समय, अदालत ने यह पता लगाने के उद्देश्य से सामग्रियों की जांच नहीं की है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, हीं लेकिन क्या इससे

दोषसिद्धि हो सकती है।- आरोपित आदेश गंभीर त्रुटि से ग्रस्त हैं और आदेश को रद्द किया

धारा 227, 239 और 245-अभियुक्तों का उन्मोचन समझाया गया

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988

धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई)-आरोप कि राज्य मंत्री अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति- जिन व्यक्तियों के नाम पर संपत्ति अर्जित की गई थी, उनके द्वारा आयकर भुगतान किया गया- ।थीं इसी तरह आरोपी एन सुरेश राजन ने अपने पिता और मां के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। आरोपमुक्त करने का आदेश पारित करते समय, इस तथ्य पर कि दो मंत्रियों के अलावा अन्य आरोपियों का आयकर निर्धारण किया गया है और आयकर का भुगतान किया गया है, आरो पी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के मद्देनजर कि कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था।- अभियुक्त व्यक्ति विशेष रूप से लगाए गए आरोप को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारिती स्वयं यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि वह वास्तव में ऐसे निर्धारिती से संबंधित है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 239.

तत्काल अपील आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत

दंडनीय अपराधों के आरोपियों को आरोप मुक्त करने के आदेश से उत्पन्न हुई, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत पारित हुई। 2014 की आपराधिक अपील संख्या 22-23 में अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में, विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को मुक्त करने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी अपील के दोनों सेटों में प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ आरोप यह था कि जब वे राज्य सरकार में सदस्य थे, तो उन्होंने अपने नाम पर और अन्य आरोपियों, अर्थात् अपने रिश्तेदारों, के नाम पर, अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्तियां अर्जित कीं।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकृत करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की योजना के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए और वह आरोपी को दोषी ठहराए बिना अपराध का संज्ञान ले सकता है और आरोपी की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को इसका पालन करना आवश्यक है।

मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संहिता) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। मुकदमा चलाने वाले विशेष न्यायाधीश को सत्र न्यायालय माना जाता है। [पैरा 15] [148-सी]

1.2 यह सामान्य बात है कि मुक्ति के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में, अदालत को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा कि

अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री का मूल्यांकन करना होगा।

और दस्तावेज़ यह पता लगाने की दृष्टि से कि क्या उनके अंकित मूल्य पर सामने आने वाले तथ्य कथित अपराध का गठन करने वाली सभी सामग्रियों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। इस स्तर पर, सामग्रियों के संभावित मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए और अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले की गहराई में जाकर यह मान ले कि ये सामग्रियां दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देंगी। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है, न कि यह कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है। यदि अदालत को लगता है कि अभियुक्त ने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकती है; हालाँकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है। [पैरा 191]

श्योराज सिंह अहलावत एवं अन्य बनाम उमर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2012 एससीआर 1034.= एआईआर 2013 एससी 52; ओंकर नोथमिश्रा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2007 (13) एससीआर 716 = (2008) 2 एससीसी 561- पर निर्भर।

सज्जन कुमार बनाम सीबी/2010 (11) एससीआर 668 = (2010) 9 एससीसी 368; दिलावर बालू कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2002 (1) एससीआर 75 = (2002) 2 एससीसी 135- अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.3 धारा 227 और 239 में पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य दर्ज करने से पहले और पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद आरोपी की जांच करने से पहले आरोपमुक्त करने का प्रावधान है। हालाँकि, दूसरी ओर, 245 को डिस्चार्ज करने का चरण, एस में संदर्भित साक्ष्य के बाद ही पहुँचा जाता है। 244 लिया गया हैसंहिता की धारा 227 के तहत, ट्रायल कोर्ट को आरोपी को बरी करना आवश्यक है यदि वह "मानती है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है"। हालाँकि, हमें 239 से मुक्त करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब "मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है"। धारा 245(1) के तहत आरोप मुक्त करने की शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब, "मजिस्ट्रेट दर्ज किए जाने वाले कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है, जिसे अगर अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है"। इस प्रकार, इन प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा में भिन्नता है। लेकिन, इन मतभेदों के बावजूद, और जो भी प्रावधान लागू हो सकता है, अदालत को इस स्तर पर यह देखने की आवश्यकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला है। [पैरा 20] [154-ई-एच; 155-ए-डीजे

आर.एसनायक बनाम ए.आरअंतुले 1936 (3) एससीआर 621 = (1986) 2 एससीसी 716- संदर्भित।

1.4 वर्तमान मामले में, आरोपमुक्त करने का आदेश पारित करते समय, इस तथ्य पर कि दो मंत्रियों के अलावा अन्य आरोपियों का आयकर निर्धारण किया गया है और आयकर का भुगतान किया गया है, आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि मंत्रियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी और इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करने के लिए अलग से कोई आय नहीं थी। आय के नाम पर संपत्ति अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकती कि वह वास्तव में ऐसे मूल्यांकनकर्ता की है।

विवादित आदेशों को पारित करते समय, अदालत ने यह पता लगाने के उद्देश्य से सामग्रियों की जांच नहीं की है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, हीं लेकिन क्या इससे दोषसिद्धि हो सकती है। हमारी राय है कि यह वह चरण नहीं था जहां अदालत को सबूतों का मूल्यांकन करना चाहिए था और आरोपी को बरी कर देना चाहिए था जैसे कि वह बरी करने का आदेश पारित कर रहा हो। इसके अलावा, जांच में दोष ही आरोपमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता। हमारी राय

में, विवादित आदेश गंभीर त्रुटि से ग्रस्त है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। अतः आदेश रद्द किया। [पैरा 21-23]

पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता द्वारा राज्य और एंटी करप्शन कुड्डालोर डिटैचमेंट बनाम केपोनुमुडी और अन्य (2007-1 एमएलजे-सीआरएल-100)- उल्टा हुआ।

पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, 2012 (1) एससीआर 1045 = (2012) 3 एससीसी563, पुंडलिक जलम पाटिल बनाम कार्यकारी अभियंता, जलगाँव मध्यम परियोजना 2008 (15) एससीआर 135 = (2008) 17 एससीसी 448-उद्धृत।

संदर्भित न्यायिक निर्णय;

(2007-1 एमएलजे-सीआरएल- 100)	उल्टा हुआ	पैरा 4
2012 (1) एससीआर 1045	उद्धृत किया गया	पैरा 8
2008 (15) एससीआर 135	उद्धृत किया गया	पैरा 9
2010 (11) एससीआर 669	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 19
2002 (1) एससीआर 75	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 20
2012 एससीआर 1034	उस पर भरोसा करें	पैरा 21
2007 (13) एससीआर 716	उस पर भरोसा करें	पैरा 21
1986 (2) एससीआर 621	संदर्भित किया गया	पैरा 22

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील का सं 22-23/2014

मद्रास उच्च न्यायालय के अपील संख्या 528/2009 तथा एमपी (एमडी) नं1/2009 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2010 से उत्पन्न।

आपराधिक अपील सं26-38/2014

रंजीत कुमार, एमएसगणेश, सोली जेसोराबजी, देवव्रत, अनूप कुमार, एमकेसुब्रमण्यम, एमयोगेश कन्ना, आरअय्याम पेरुमल, केशेषाचारी, अनुश्री कपाडिया, सुकुन केएसचंदेले, आरनेदुमारन, मूवीता, मेहरवाज़, शौनक, पक्षकारों की तरफ से

न्यायालय का निर्णय चंद्रमौली केआरप्रसाद, जे द्वारा दिया गया था।

आपराधिक आवेदन सं22-23 वर्ष 2014 (@स्पेशल लीव पिटीशन (सीआरएल.) सं..3810-3811 वर्ष 2012)

1. 2009 के आपराधिक आरसीनंबर 528 और 2009 के आपराधिक एमपी (एमडी) नंबर 1 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10 दिसंबर, 2010 के आदेश जिसमें विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-विशेष न्यायाधीश, नागरकोइल (बाद में 'विशेष न्यायाधीश' के रूप में संदर्भित) द्वारा 25 सितंबर, 2009 पारित आदेश जिससे उन्होंने उत्तरदाताओं को मुक्त

करने से इनकार कर दिया, से व्यथित होकर तमिलनाडु राज्य ने विशेष याचिकाएं प्रस्तुत की।

2. अनुमति दी गई.

3. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 1, एन सुरेश राजन , 13.05.1996 से 14.05.2001 की अवधि के दौरान, तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य और पर्यटन राज्य मंत्री भी थे। प्रतिवादी संख्या 2, केनीलकंडा पिल्लई उनके पिता हैं और प्रतिवादी संख्या 3, आर.राजम, उनकी मां हैं। एक सूचना के आधार पर कि एन सुरेश राजन पर्यटन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, सुरेश राजन ने अपने नाम पर और अपने पिता और माता के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन और संपत्ति अर्जित की थी, अपराध संख्या 7, 2002 14 मार्च, 2002 को कन्याकुमारी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मंत्री एन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था । सुरेश राजन , उनके पिता, माता, बड़ी बहन और बहनोइ। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने एन सुरेश राजन ने मंत्री रहते हुए अपने नाम पर और दूसरों के नाम पर के कब्जे में संपत्ति और आर्थिक संसाधनों के संबंध में जानकारी एकत्र की । मंत्री की उनके ज्ञात स्रोतों से आय और उनके द्वारा किए गए व्यय की गणना करने पर, यह पाया गया कि उनके स्वामित्व और स्वामित्व वाली संपत्तियाँ उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से

रु23,77,950.94 अधीक है।जांच अधिकारी ने न केवल आरोपी मंत्री बल्कि उनके पिता और मां और उनकी बहन और बहनोई से भी पूछताछ की। अंततः, जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जांच अवधि के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1, एन । सुरेश राजन ने नाम पर और अपने पिता, केनीलकंडा पिल्लई (प्रतिवादी नंबर 2) और मां आरराजम (प्रतिवादी नंबर 3) और उसकी पत्नी डीएस भारती के नाम पर रुपये का मूल्य 17,58,412.47 की आर्थिक संसाधनों और संपत्तियों का अधिग्रहण किया है और उन पर कब्जा कर रखा है।जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि मंत्री के पिता और माता के पास उनके नाम पर अर्जित संपत्ति और आर्थिक संसाधनों के अनुरूप आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। तदनुसार, जांच अधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1, मंत्री और उनके पिता (प्रतिवादी नंबर 2) और मां (प्रतिवादी नंबर 3) के खिलाफ धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ई) के साथ पठित के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए 4 जुलाई, 2003 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया।। उत्तरदाताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 239 के तहत 5 दिसंबर, 2003 को आवेदन दायर किया, जिसमें उन्हें उन्मोिचत करने की मांग की गई। विशेष न्यायाधीश ने 25 सितंबर 2009 के अपने आदेश से उनकी प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। ऐसा करते समय, विशेष न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"इस स्तर पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि राज्य के पास उनके खिलाफ कोई आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है और यह इस अदालत की राय में कानून के अनुसार नहीं होगा।साथ ही यह पता चला है कि तीन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने के उद्देश्य से बुनियादी सामग्रियां हैं, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई है और इस आशय के आदेश पारित किए गए हैं।"

4. इससे व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा विशेष न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था और उत्तरदाताओं को इस निष्कर्ष पर बरी कर दिया था कि इस सामग्री के अभाव में कि प्रतिवादी नंबर 1 से उसकी माँ और पिता को पैसा दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है अपने बेटे की ओर से संपत्ति और संसाधनों को अपने नाम पर रखा है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कुड्डालोर डिटैचमेंट बनाम केपोनुमुदी और अन्य.1 (2007-1MLJ-CRL.-100) द्वारा राज्य के मामले में अपने पहले के फैसले पर बहुत भरोसा किया। , जिसकी वैधता संबंधित अपीलों में भी विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देते हुए इस प्रकार कहा:

"12 वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं 2 और 3, अर्थात् ए 2 और ए 3 के नाम पर मौजूद संपत्तियों को ए 2 के व्यक्तिगत आय संसाधनों की किसी भी जांच के अभाव में पहले आरोपी की संपत्ति या संसाधन नहीं माना जा सकता है। और A3 इसके अलावा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि A2 एक सेवानिवृत्त हेड मास्टर था जो पेंशन प्राप्त कर रहा था और A3 एक वित्तीय संस्थान चला रहा था और एक आयकर निर्धारिती था। यह दिखाने के लिए किसी सामग्री के अभाव में कि A1 का पैसा A2 और A3 के हाथों में चला गया, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पहले आरोपी की ओर से संपत्तियों और संसाधनों को अपने नाम पर रखा है। यह दिखाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है कि A2 और A3 ने A1 को उसकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति और संसाधन हासिल करने के लिए उकसाया।

इन्हीं परिस्थितियों में अपीलकर्ता हमारे सामने है।

आपराधिक अपील संख्या 26-38 / 2014(@ स्पेसल लीव पीटिशन (सीआरएल) संख्या 134-146/2013)

5. ये विशेष अनुमति याचिकाएँ परिसीमा द्वारा वर्जित हैं। याचिकाएं दाखिल करने में 1954 दिन और दोबारा दाखिल करने में 217 दिन की देरी

हुई है। विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल करने और दोबारा दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर किए गए हैं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार का कहना है कि विशेष अनुमति याचिका दायर करने में देरी हुई है क्योंकि लोक अभियोजक ने पहले राय दी थी कि यह उपयुक्त मामला विशेष अनुमति याचिका दायर करने लायक नहीं है। सरकार ने राय स्वीकार कर ली और विशेष अनुमति याचिका दायर न करने का निर्णय लिया। यह इंगित किया गया है कि उसी सरकार ने जिसमें एक आरोपी मंत्री था, विशेष अनुमति याचिका दायर न करने का उपरोक्त निर्णय लिया था। हालाँकि, सरकार बदलने के बाद, महाधिवक्ता से राय मांगी गई, जिन्होंने कहा कि यह उपयुक्त मामला है जिसमें दिए गए आदेश को चुनौती दी जानी चाहिए। तदनुसार, देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण है।

7. हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अिधवक्त श्री सोली जेसोराबजी का कहना है कि केवल सरकार का परिवर्तन ही अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उनका कहना है कि सरकार बदलने के साथ, कई मुद्दे जो अंतिम रूप ले चुके हैं, लंबे विलंब के बाद फिर से खुलेंगे, जिनकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके अनुसार, इस आधार पर भारी देरी को माफ करना कि उत्तराधिकारी सरकार, जो एक अलग राजनीतिक दल से संबंधित है, ने विशेष अनुमति याचिका

दायर करने का निर्णय लिया था, एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम होगी और इससे न्याय का वध जाएगा। वह इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक कानूनी उपाय के लिए एक समय सीम होती है और देरी को माफ करना एक अपवाद है।3 पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड,2 (2012) 3 एससीसी 56 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है , और हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 29 की ओर आकर्षित किया गया है, जो इस प्रकार हैंः

> "29 हमारे विचार में, यह सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और सहायक संस्थाओं को सूचित करने का सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है, तब तक फ़ाइल के सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियागत लालफीताशाही के कारण इसे कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभागों पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ करें। देरी की माफ़ी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कानून सभी को एक ही रोशनी में आश्रय देता है और इसे कुछ लोगों के लाभ के लिए नहीं घुमाया जाना चाहिए।

8. श्री सोराबजी ने आगे कहा कि सीमा अधिनियम सरकार के लिए कानून के तहत प्रदान किए गए उपाय का सहारा लेने के लिए अलग-अलग समय सीमा का प्रावधान नहीं करता है और मामला उसके अधिकारियों या एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी या मिलीभगत का मामला नहीं है। इतनी बड़ी देरी माफ़ करने योग्य नहीं है। पुंडलिक जालम पाटिल बनाम कार्यकारी अभियंता, जलगांव मीडियम प्रोजेक्ट, 3 (2008) 17 एससीसी 448 के मामले में भी इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है और फैसले के पैराग्राफ 31 का संदर्भ दिया गया है, जो इस प्रकार है। :

> "31 यह सच है कि जब राज्य और उसकी संस्थाएं देरी की माफी मांगने वाले आवेदक हैं तो वे कुछ निश्चित छूट के हकदार हो सकते हैं लेकिन सीमा का कानून नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए समान है। परिसीमा अधिनियम सरकार को अपील या आवेदन दायर करने के लिए अलग अवधि का प्रावधान नहीं करता है। यह एक अलग मामला होगा जहां सरकार एक ऐसा मामला बनाती है जहां सार्वजनिक हित को उसके अधिकारियों या एजेंटों की ओर से धोखाधड़ी या मिलीभगत के कृत्यों के कारण

नुकसान हुआ दिखाया गया था और जहां अधिकारी स्पष्ट रूप से इसके साथ विपरीत उद्देश्यों में थे। किसी दिए गए मामले में यदि ऐसे किसी भी तथ्य की वकालत की जाती है या साबित किया जाता है तो उन्हें विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है और वे कारक न्यायिक फैसले में जा सकते हैं। वर्तमान मामले में, ऐसे किसी भी तथ्य को प्रस्तुत या साबित नहीं किया गया है, हालांकि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा मिलीभगत और धोखाधड़ी का सुझाव देने का एक कमजोर प्रयास किया गया था, लेकिन बिना किसी आधार के। दलीलों में कोई उचित आधार न होने पर हम बार में की गई दलीलों पर विचार नहीं कर सकते।"

9. श्री सोराबजी द्वारा प्रस्तुत तर्क वजनदार हैं, विचारणीय हैं और एक समय हम देरी की माफी के लिए दायर आवेदनों को खारिज करने और विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने के इच्छुक थे। हालाँकि, दूसरे विचार पर हम पाते हैं कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं में लगाए गए आदेश की वैधता को विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3810-3811 से उत्पन्न होने वाली आपराधिक अपीलों में जाना होगा और इसके सामने , परिसीमा के आधार पर इन विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करना नासमझी होगी। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3810-3811 वर्ष 2012,

तमिलनाडु राज्य द्वारा िनरीक्षक पुलिस, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक बनाम एन । सुरेश राजन और अन्य द्वारा उत्पन्न आपराधिक अपीलों में लगाया गया आदेश।, मुख्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कुड्डालोर डिटैचमेंट बनाम केपोनमुडी और अन्य (2007-1MLJ-CRL.-100) द्वारा राज्य में निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जो है वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं में इसका विरोध किया गया है। दरअसल, 3 जनवरी 2013 के आदेश द्वारा इन याचिकाओं को उपरोक्त विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ सुने जाने का निर्देश दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, हम विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल करने और दोबारा दाखिल करने में हुई देरी को माफ करते हैं।

10. इन याचिकाओं में तमिलनाडु राज्य ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 11 अगस्त, 2006 के आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसके तहत विशेष न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विल्लुपुरम (इसके बाद 'विशेष न्यायाधीश' के रूप में संदर्भित), 2003 के विशेष मामले संख्या 7 में, बर्खास्त कर दिया गया है द्वारा पारित 21 जुलाई, 2004 के आरोपमुक्त करने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गई थीं। , ।

11.याचीका स्वीकृत.

12. अनावश्यक विवरणों से रहित, वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि केपोनुमुदी, प्रतिवादी नंबर 1, जांच अवधि के दौरान

राज्य विधान सभा के सदस्य और तमिलनाडु सरकार में राज्य मंत्री थे। पीविशालाक्षी पोनमुडी (प्रतिवादी नंबर 2) उनकी पत्नी हैं, जबकि पी.सरस्वती (प्रतिवादी नंबर 3) (मृतक के बाद से) उनकी सास थीं। ए.मणिवन्नन (प्रतिवादी संख्या 4) और ए.नंदगोपाल (प्रतिवादी संख्या 5) (मृत्यु के बाद से) मंत्री (प्रतिवादी संख्या 1) के मित्र हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 अपने जीवनकाल के दौरान एक सिगा एजुकेशनल ट्रस्ट, विल्लुपुरम के ट्रस्टी थे।

13. वर्तमान अपीलों में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित उन्मोचन के आदेश की वैधता की जांच करनी है। इसलिए, हम इस स्तर पर अभियोजन या प्रतिवादी के बचाव के मामले के विवरण में जाना अनावश्यक मानते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13.05.1996 से 30.09.2001 की अवधि के दौरान परिवहन मंत्री और तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य के रूप में केपोनमुडी (प्रतिवादी नंबर 1) के अधिग्रहण व नाम पर और उसकी पत्नी और बेटों के नाम पर आर्थिक संसाधनों और संपत्तियों का कब्ज़ा था, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। तदनुसार, 2002 का अपराध संख्या 4 भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कुड्डालोर गांव में 14 मार्च 2002 को भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के साथ धारा 13(2) और धारा 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा के तहत दर्ज किया गया था। । जांच के दौरान पता चला कि

13.05.1996 से 31.03.2002 की अवधि के बीच, मंत्री ने मथिरीमंगलम, कास्पकरनई, कप्पियामपुलियूर गांवों और विल्लुपुरम तालुक के अन्य स्थानों, विट्टलापुरम गांव और थिंडीवनम तालुक के अन्य स्थानों , कुड्डालोर और पांडिचेरी कस्बों में, चेन्नई और त्रिची शहरों में और अन्य स्थानों पर संपत्तियां अर्जित कीं और अपने पास रखीं। । यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1-मंत्री ने एक लोक सेवक होने के नाते अपने नाम पर और अपनी पत्नी, सास-ससुर के नाम पर आर्थिक संसाधनों और संपत्तियों को अर्जित करके और उन पर कब्जा करके आपराधिक कदाचार का अपराध किया है। सिगा एजुकेशनल ट्रस्ट का नाम, प्रतिवादी नंबर 1, मंत्री की ओर से अन्य उत्तरदाताओं के पास था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 3,08,35,066.97 रुपये तक अधिक था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह संपत्ति का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके और इस तरह, मंत्री ने अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराध किया था।

14.जांच के दौरान, यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान और ऊपर बताए गए स्थानों पर, अन्य आरोपियों ने मंत्री को उनके द्वारा अपराध करने में उकसाया था। प्रतिवादी संख्या 2, मंत्री की पत्नी, ने उनकी ओर से संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम के साथ-साथ मेसर्स विसाल एक्सपो, जिसकी वह एकमात्र मालिक थी के नाम पर रखकर अपराध को अंजाम देने में सहायता की। । इसी तरह, प्रतिवादी

नंबर 3, सास ने मंत्री की ओर से संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम के साथ-साथ सिगा एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर रखकर मंत्री की सहायता की। इसी प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 5 ने मंत्री की सहायता की और उनकी ओर से इसके ट्रस्टी होने का दावा करते हुए सिगा एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा रखा। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जांच के दौरान, अन्य सभी आरोपियों के बयान लिए गए थे और जांच एजेंसी की राय में, उनके बयानों की उचित जांच और आगे के सत्यापन के बाद, मंत्री संतोषजनक ढंग से जवाब देने में सक्षम नहीं थे। आय से अधिक संपत्ति की मात्रा तदनुसार, राज्य सरकार के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

15.यहां यह बताना प्रासंगिक है कि अधिनियम की योजना के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायाधीश द्वारा की जानी है और वह आरोपी की प्रतिबद्धता के बिना अपराध का संज्ञान ले सकता है और आरोपी की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया इसका पालन करना आवश्यक है।। मुकदमा चलाने वाले विशेष न्यायाधीश को सत्र न्यायालय माना जाता है। उत्तरदाताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ संहिता की धारा

239 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए याचिका दायर की कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की आय का पता लगाने के लिए जिस प्रणाली का पालन किया था वह गलत है। प्रारंभ में चेक की अवधि 10.05.1996 से 13.09.2001 तक थी जिसे जांच के दौरान 13.05.1996 से बढ़ाकर 31.03.2002 कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी के मुताबिक, आय को कम आंका गया और खर्च को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। प्रतिवादी नंबर 1, मंत्री के अनुसार, उनकी पत्नी और उनकी सास की व्यक्तिगत संपत्ति की आय और उनके व्यय को उनकी संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए था। उनके मुताबिक, यह आरोप गलत है कि उनके नाम पर मौजूद संपत्तियां उनकी बेनामी संपत्ति हैं। यह भी तर्क दिया गया कि संपत्तियों का मूल्यांकन प्रतिवादी नंबर 1 की संपूर्ण आय और व्यय को ध्यान में रखे बिना किया गया है। प्रतिवादियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी, जो मामले के मुखबिर हैं, ने निरंकुश तरीके से काम किया है और उनका कार्य पूर्वाग्रह से ग्रसित है। विशेष न्यायाधीश ने इन सभी दलीलों की जांच की और 21 जुलाई, 2004 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को इस निष्कर्ष पर बरी कर दिया कि जांच ठीक से नहीं की गई थी। विशेष न्यायाधीश ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की संपत्ति का मूल्य प्रतिवादी संख्या 1 की व्यक्तिगत संपत्तियों और आय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए था और ऐसा करने से प्रतिवादी संख्या 1 की संपत्ति नहीं जोड़ी जा सकती। यह उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन माना जाएगा।

उपरोक्त निष्कर्ष पर विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। इससे व्यथित होकर, तमिलनाडु राज्य ने अलग-अलग पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर कीं और उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश द्वारा, सभी पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त करने के आदेश की पुष्टि करते हुए माना कि अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी नंबर 1 की आय में अन्य उत्तरदाताओं की आय, जिनका आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन किया गया था, जोड़कर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय की राय में, अंतिम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने का कोई आधार नहीं बनेगा। ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "18 वे संपत्तियाँ, जो स्वीकृत रूप से अभियुक्त 1 की नहीं हैं और आय के स्वतंत्र स्रोत वाले व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, जिनका मूल्यांकन आयकर अधिनियम के तहत किया जाता है, उन्हें अभियुक्त -1 की संपत्ति के रूप में जोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाई गई ऐसी प्रक्रिया न केवल अमान्य है बल्कि अवैध भी है। अंतिम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने का कोई आधार नहीं बनेगा। आय के ज्ञात स्रोत के संदर्भ में

अनुपातहीन संपत्ति स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाई गई पद्धति बिल्कुल गलत है।

बेनामी का सिद्धांत विश्वास की अवधारणा से पूरी तरह से अलग है और आरोपी संख्या तीन से पांच को संपत्तियों के धारकों के रूप में वर्गीकृत करना या कि वे आरोपियों के बेनामी हैं, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा बेनामी लेन-देन को वास्तविक चरित्र की कानूनी रूप से अनुमत सामग्री का उत्पादन करके साबित किया जाना चाहिए जो सीधे तौर पर बेनामी के तथ्य को साबित करेगा और इस संबंध में सामग्री की पूरी कमी है और इसलिए बेनामी का सिद्धांत भी स्थापित नहीं किया गया है। किसी भी सबूत से दूरप्रथम दृष्टया साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अन्य अभियुक्तों के पास अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए पर्याप्त धनराशि है और A1 का उन संपत्तियों से कोई लेना-देना नहीं है और उनसे किए गए अधिग्रहण की आय का स्रोत बताने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अन्य व्यक्ति.

19 ..... माना कि अभियुक्तों के पास ट्रस्ट के नाम पर मौजूद संपत्तियों का स्वामित्व नहीं है और अभियुक्त A3 से A5 द्वारा नियंत्रित हैं। ट्रस्ट एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है

जिसका मूल्यांकन आयकर और संपत्तियों के स्वामित्व के लिए किया जाता है। केवल संपत्ति के मूल्य को बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष ने A1 के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के लिए ट्रस्ट के ट्रस्टियों को आरोपी संख्या तीन से पांच के रूप में सूचीबद्ध किया।

21 .....ए 2 और ए 3 द्वारा अपनी व्यक्तिगत आय से अर्जित की गई सभी संपत्तियों को आयकर रिटर्न में दिखाया गया है, जो तथ्य अभियोजन पक्ष को भी पता है और अभियोजन के रिकॉर्ड में भी उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष के पास अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते समय ऐसी आय को अस्वीकार करने के लिए उन आयकर रिटर्न की उपेक्षा करने का कोई औचित्य या कारण नहीं है। अब रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेज़ भी बेनामी लेनदेन के दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर देंगे।

उच्च न्यायालय ने अंततः इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

"24.....इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने उन सामग्रियों और दस्तावेजों का विश्लेषण किया जो आरोप तय करने के चरण में और उनके अंकित मूल्य पर उपलब्ध कराए गए थे, सही

निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्तरदाताओं/अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय नहीं किए जा सकते"

16. अब हम इन अपीलों की पृष्ठभूमि में उन पर लगाए गए आदेशों की मुक्ति और वैधता के मुद्दे से संबंधित कानूनी स्थिति पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्री रंजीत कुमार का कहना है कि विवादित आदेश अवैधता से ग्रस्त है। वह बताते हैं कि आरोप तय करने के समय दायरा सीमित है और इस स्तर पर जो देखा जाना है वह यह है कि एकत्र की गई सामग्रियों और दस्तावेजों की जांच करने पर आरोप को निराधार कहा जा सकता है या नहीं। उनका कहना है कि इस स्तर पर, अदालत सबूतों का मूल्यांकन नहीं कर सकती जैसा कि मुकदमे के समय किया जाता है। वह बताते हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय, साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है और अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया गया है, जैसा कि अभियुक्त को बरी करते समय मुकदमे के बाद किया जाता है।

17. श्री सोराबजी और उत्तरदाताओं-अभियुक्तों की ओर से उपिस्थत श्री एन वी गणेश ने कहा कि जब अदालत आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करती है, तो उसे यह पता लगाने के लिए सामग्री की जांच करनी होती है कि लगाया गया आरोप निराधार है या नहीं। उनका कहना है कि आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करते समय अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों की जांच और वजन करने से कोई नहीं

रोकता है कि एकत्र की गई सामग्रियों और दस्तावेजों के आधार पर लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं। उनका यह भी तर्क है कि अदालत ऐसे आवेदन पर विचार करते समय केवल एक पोस्ट-ऑफिस या अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, सज्जन कुमार बनाम सीबीआई,4 (2010) 9 एससीसी 368 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है और हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 17(4) की ओर आकर्षित किया गया है, जो इस प्रकार पढ़ता है:

> "17 भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य, 1979 (3) एससीसी 4 में , धारा 227 सीआरपीसी के दायरे पर विचार किया गया था। विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों की गणना की है:
>
> (4) संहिता की धारा 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायाधीश, जो वर्तमान संहिता के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी अदालत है, केवल एक डाकघर या अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे इसकी व्यापक संभावनाओं पर विचार करना होगा। मामला, अदालत के समक्ष पेश किए गए

सबूतों और दस्तावेजों का कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली कोई बुनियादी कमज़ोरियाँ इत्यादि। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष की गहन जाँच करनी चाहिए और सबूतों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह कोई सुनवाई कर रहा हो।

18. एक और निर्णय जिस पर भरोसा किया गया है वह दिलावर बालू कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य,5 (2002) 2 एससीसी 135 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है, उक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ का संदर्भ दिया गया है :

"12 अब अगला सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कानून की स्थापित स्थिति यह है कि न्यायाधीश के पास उक्त धारा के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय निष्कर्ष निकालने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को छांटने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है। यह पता लगाना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं; जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से

समझाया नहीं गया है, अदालत को आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से उचित ठहराया जाएगा; कुल मिलाकर यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट है कि उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य कुछ संदेह पैदा करते हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह नहीं है, तो उसके लिए आरोपी को आरोप मुक्त करना और धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना पूरी तरह से उचित होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अनुसार, न्यायाधीश केवल एक डाकघर या अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य के कुल प्रभाव और अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए। मामले के पक्ष-विपक्ष की घूम-घूम कर जांच न करें और सबूतों को ऐसे तौलें जैसे कि वह कोई मुकदमा चला रहे हों।"

19. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपना ध्यान दिया है और श्री रंजीत कुमार द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ हमारी सराहना करती हैं। यह सच है कि आरोपमुक्त करने के आवेदनों पर विचार के समय, अदालत अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकती है या पोस्ट-ऑफिस के रूप में कार्य नहीं कर सकती है और यह पता लगाने के लिए सबूतों की जांच कर

सकती है कि लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं। ताकि सेवामुक्ति का आदेश पारित किया जा सके। यह सामान्य बात है कि आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार के चरण में, अदालत को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए करना होगा कि क्या तथ्य सही हैं। उनके अंकित मूल्य पर उभरने से कथित अपराध का गठन करने वाली सभी सामग्रियों के अस्तित्व का खुलासा होता है। इस स्तर पर, सामग्रियों के संभावित मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए और अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले की गहराई में जाकर यह मान ले कि ये सामग्रियां दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देंगी। हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है, न कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है। इसे अलग ढंग से कहें तो, अगर अदालत को लगता है कि आरोपी ने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकती है; हालाँकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है। इस संबंध में श्योराज सिंह अहलावत और अन्य के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 6 एआईआर

2013 एससी 52 , जिसमें, बिंदु पर विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने ओंकार नाथ मिश्रा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 7 (2008) में लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण का समर्थन किया ।) 2 एससीसी 561 :

> "11 यह सामान्य बात है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर लेने पर, सभी घटकों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। कथित अपराधउस स्तर पर, अदालत से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के संभावित मूल्य की गहराई में जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है और अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं बनाया गया है। उस स्तर पर, सामग्री पर स्थापित मजबूत संदेह भी, जो अदालत को कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक अवयवों के अस्तित्व के बारे में अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है, उस अपराध के संबंध में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने को उचित ठहराएगा।"

20. अब सज्जन कुमार (सुप्रा) और दिलावर बालू कुराने (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर लौटते हुए, जिन पर उत्तरदाताओं ने भरोसा किया था, हमारी राय है कि वे अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उपरोक्त निर्णय संहिता की धारा 227 के प्रावधान पर विचार करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि आरोपमुक्त करने के चरण में न्यायालय मामले के पक्ष और विपक्ष में घूम-घूमकर जांच नहीं कर सकता है और सबूतों को ऐसे नहीं तौल सकता है जैसे कि वह कोई मुकदमा चला रहा हो। यह उल्लेखनीय है कि संहिता अपने द्वारा विचारणीय मामले में धारा 227 के तहत सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोप मुक्त करने पर विचार करती है; पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए मामले धारा 239 के अंतर्गत आते हैं और पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा शुरू किए गए मामलों को धारा 245 में निपटाया जाता है। उपरोक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उनमें किसी आरोपी को आरोप मुक्त करने के संबंध में कुछ अलग प्रावधान हैं। संहिता की धारा 227 के तहत, ट्रायल कोर्ट को आरोपी को आरोपमुक्त करना आवश्यक है यदि वह "मानती है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है"। हालाँकि, धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब "मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है"। आरोपमुक्त करने की शक्ति धारा 245(1) के तहत प्रयोग की जा सकती है, जब, "मजिस्ट्रेट दर्ज किए जाने वाले कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया

है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा"। धारा 227 और 239 में पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य दर्ज करने से पहले और पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद आरोपी की जांच करने से पहले आरोपमुक्त करने का प्रावधान है। हालाँकि, दूसरी ओर, धारा 245 के तहत आरोपमुक्त करने का चरण, धारा 244 में संदर्भित साक्ष्य लेने के बाद ही पहुँचा जाता है। इस प्रकार, इन प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा में अंतर है। लेकिन, हमारी राय में, इन मतभेदों के बावजूद, और जो भी प्रावधान लागू हो सकता है, अदालत को इस स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला है। इस संबंध में आरएस नायक बनाम एआर अंतुले के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। वही इस प्रकार है:

> "43 .....स्थिति में इस अंतर के बावजूद इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस चरण में मजिस्ट्रेट को धारा 245(1) के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करना आवश्यक है वह प्रारंभिक और परीक्षण है और "प्रथम दृष्टया" मामला लागू किया जाना चाहिए। तीनों धाराओं की भाषा में अंतर के बावजूद, कानूनी स्थिति यह है कि यदि ट्रायल कोर्ट संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो आरोप तय करना होगा।

21. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां आरोपी मंत्री (प्रतिवादी नंबर 1) केपोनमुडी के खिलाफ आरोप यह है कि जब वह तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य और राज्य मंत्री थे, तब उन्होंने अपने नाम पर संपत्ति अर्जित की थी और उस पर उनका कब्जा था। पत्नी और उसकी सास भी, जो अपने अन्य दोस्तों के साथ, सिगा एजुकेशनल ट्रस्ट, विल्लुपुरम से थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिगा एजुकेशनल ट्रस्ट, विल्लुपुरम की संपत्तियों पर आरोपी मंत्री की ओर से अन्य आरोपियों का कब्जा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये संपत्तियाँ वास्तव में के.पोनुमुदी की संपत्तियाँ थीं। इसी तरह आरोपी एन सुरेश राजन ने अपने पिता और मां के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। आरोपमुक्त करने का आदेश पारित करते समय, इस तथ्य पर कि दो मंत्रियों के अलावा अन्य आरोपियों का आयकर निर्धारण किया गया है और आयकर का भुगतान किया गया है, आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के मद्देनजर कि कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था। इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए अलग आय। आयकर निर्धारिती के नाम पर मौजूद संपत्ति यह मानने का आधार नहीं हो सकती कि वह वास्तव में ऐसे करदाता की है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारी राय में, इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। यह भ्रष्ट लोक सेवकों को

ज्ञात व्यक्तियों के नाम पर संपत्ति इकट्ठा करने, उनकी ओर से आयकर का भुगतान करने और फिर कानून की पकड़ से बाहर रहने का अवसर देगा। आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय, अदालत ने यह पता लगाने के उद्देश्य से सामग्रियों की जांच नहीं की है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, लेकिन क्या इससे दोषसिद्धि हो सकती है। हमारी राय है कि यह वह चरण नहीं था जहां अदालत को सबूतों का मूल्यांकन करना चाहिए था और आरोपी को बरी कर देना चाहिए था जैसे कि वह बरी करने का आदेश पारित कर रहा हो। इसके अलावा, जांच में दोष ही आरोपमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता। हमारी राय में, विवादित आदेश गंभीर त्रुटि से ग्रस्त है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

22. इस फैसले में हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी इन अपीलों के निपटान के उद्देश्य से है और इसका मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा। जीवित उत्तरदाताओं को 3 फरवरी, 2014 को संबंधित अदालतों के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। अदालत कानून के अनुसार आरोप के चरण से मुकदमे को आगे बढ़ाएगी और इसे शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करेगी।

23. परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उपरोक्त टिप्पणी के साथ आरोपमुक्त करने के आदेश को रद्द करते हैं।

याचिका स्वीकृत ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कार्तिक शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।